स्थापना का प्रयोजन आवास, गन्दी बस्ती सुधार, शहरी विकास आदि में कार्यरत व्यवसायिकों के लिये प्रशिक्षण और अनुसंधान-सहायता मुहैया करना और प्रशासकों व्यवसायिकों अनुसंधानकर्त्ताओं तथा अन्यों के लिये पारस्परिक कार्य का एक मंच स्थापित करना है। यह संस्था (एच० एम० एम० आई०) आवास तथा मानव बस्ती के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था के रूप में कार्य करता है, विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विशिष्ट राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है और आवास तथा मानव बस्तियों के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायिकों की तकनीकी तथा प्रबंधकीय दक्षता में उन्नयन करने के लिये नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

(ग) यह संस्थान मकानों के निर्माण का कार्य नहीं करता।

Foodgrains stock position of FCI in Tripura

1154. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the total stock of foodgrains available in godowns of FCI in Tripura during the 1990, godown-wise;

(b) the quantity of foodgrains declared unfit for human consumption lying in different godowns in Tripura; and

(c) whether Government are aware of the fact that starvation have started in tribal areas of the State due to non-supply of foodgrains by the ration shops?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) A quantity of 12592 M.T.s of foodgrains (Rice-11197 M.Ts and wheat-1395 Tonnes) is lying in stocks of F.C.I. at present in various godowns in Tripura. However, godown-wise stock position is not available.

(b) Total quantity of 0.122 Metric tonnes of wheat and 48.950 M.T.s of rice was lying as damaged and unfit for human consumption as on 1-7-1990.

(c) Central Government issues foodgrains to the State Government for meeting the requirements of public distribution system, which is only supplemental to the open market availability. State Government/U.T., is responsible for implementing the Public Distribution Scheme. However, Central Government is not aware of any non-supply of foodgrains by ration shop.

Demands of Anganwadi Workers

1155. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the demands of Anganwadi Workers regarding minimum wages etc; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN). (a) and (b) No, Sir. The anganwadi workers and helpers have submitted representations to Government demanding status of Government employees and remunerations equal to minimum wages. Since Integrated Child Development Services Programme has been visualised on principle of community participation and these functionaries are part-time ($4\frac{1}{2}$ hrs. daily), Voluntary Workers selected from the local community, any of these two demands are not possible to be met.

देश में भवन निर्माण सामग्री की कमी

1156. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में भवन निर्माण की महत्वपूर्ण सामग्रियों का अभाव है, यदि हां, तो विभिन्न प्रकार की भवन

निर्माण सामग्रियों की कमी के संबंध में आकलन क्या है और इन कमियों को कब तक दूर कर लिया जाएगा ; और

(ख) क्या इन कमियों का एक कारण यह भी है कि इन भवन सामग्रियों का बड़ा हिस्सा गगनचुम्बी भवनों तथा विशाल और विलासतापूर्ण महलों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कानून/नियम बनाकर मध्यम आय वर्ग समूह के मकानों से बड़े मकानों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 8वीं योजना कार्यों के भाग के रूप में, वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्रियों की मांग और सम्भावित कमी का आकलन किया गया है । ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान आवास के लिए महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्रियों की मांग/उपलब्धता :

21.77 मिलियन रिहायशी एकक (नव निर्माण 17.97 रिहायशी एकक-3.80 रिहायशी एककों का उन्नयन)

सामग्री	मात्रा		
	मांग	उपलब्धता (मिलियन टन)	कमी
1. सीमेंट	131.98	4.9	17.05
2. इस्पात	13.94	11.2	2.70
3. ईंटें	286496	231591	54899
4. मिलावा (एग्रीगेट)	555.94	270.3	285.59
5. इमारती लकड़ी	29.09	15.7	13.34

जबकि सीमेंट और इस्पात की कमी पर कुछ प्रयासों से काबू पाया जा सकता है, ईंट, मिलावा (एग्रिगेट) और इमारती लकड़ी की कमी अत्यधिक होने की सम्भावना है। इस विकट स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने बैंकों पर निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार के विभिन्न उपाय किए हैं । प्रवर्तित भवन निर्माण सामग्रियों तथा घटकों के विकास, उत्पादन और लागू करने में समन्वय करने के लिए भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद का गठन किया गया है ।

(ख) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में उत्तरोत्तर निर्माण कार्यक्रमों के कारण, भवन निर्माण सामग्रियों की मांग में वृद्धि हुई है जिससे मांग तथा पूर्ति में अन्तर बढ़ा है । राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में विलासपूर्ण निर्माणों में दुर्लभ संसाधनों के विचलन को रोकने की अपेक्षा की गई है । नीति संबंधी प्रारूप दस्तावेज में यह भी विचार किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय विसंगतियों के लिये छूट सहित अधिकतम और न्यूनतम आवास मानदण्ड निर्धारित होंगे । विभिन्न आकार के प्लाटों और रिहायशी एककों पर समुचित न्यूनतम और अधिकतम आवास मापदण्ड स्थानीय परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वार निर्धारित किए जायेंगे ।

Encroachment on public property in Dehli

1157. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the percentage of rise in the encroachment of public land, roads and footpaths in Delhi during 1989 and 1990 till date;